

FORM- II  
(For projects other than linear projects)  
Government of Chhattisgarh  
Office the District Collector Narayanpur (C.G.)

No./Colt./R-I/2020/283/Narayapur

DATE - 25/06/2020

TO WHOWHOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 66.020 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Shri Bajrang Powar & Ispat Limited, For Mining Lease area and Approach Road in Narayapur district** falls within jurisdiction of **Dhanora & Kodoli** villages in **Narayapur Tehsil**.

It is further certified that.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 66.020 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-division Level committee and the District Level Committee are enclosed as annexure – A to D
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) Each of the concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversi
- (d) on. A copy of certificate issued by the gram sabha of Dhanora & Kodoli villages(s) is enclosed as annexure - B to annexure - C
- (e) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram sabha present.
- (f) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (g) The rights of primitive Tribal Groups And pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safe guarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl..As above

25/06/2020  
(Abhijeet Singh)  
Collector  
District - Narayanpur  
*[Signature]*

## શ્રીમતી પંચાયત કલોક

B

संविद्

Book No.  
उत्तरपत्र  
१९८५ अगस्त - १९८६



(A)

प्रदर्श - ब

ग्राम सभा - छोटीरा की बैठक दिनांक 21/09/2016 का कार्यवाही विवरण  
ग्राम छोटीरा  
स्थान छोटीरा

आज दिनांक 21/09/2016 को ग्राम छोटीरा के सरपंच श्री/श्रीमती अदिता मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहुत की गयी है। इस बैठक में ग्राम सभा का वन समिति छोटीरा के सदस्य 80% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की गई :-

- ग्राम छोटीरा में आदेक/एजेंसीश्री विजय यस्तर लिंग्स (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपर्वतन हेतु 52.020 हेक्टर वनभूमि तथा 0 है। राजस्व वनमूमि, कुल 4.020 है। वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपर्वतित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।
- इस वन व्यपर्वतन प्रकरण के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि लौट आमलु रखना रखना अधिकार के व्यपर्वतन के लिए प्रस्तावित है, मैं कोई भी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वनमूमि पर कृदि कार्य आवास या अन्य पारम्पारिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यवितरण या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया यथा है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारिक का नाम	रकम (ड.मे)
1	छोटीरा	निरुल	निरुल

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में नियम लिया गया है कि 52.020 है। वनमूमि तथा 0 है। राजस्व वनमूमि कुल योग 52.020 है, वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेससे (आदेक/एजेंसी विजय यस्तर लिंग्स) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपर्वतित की जाय।

संलग्न - ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1) मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री

संरक्षण

हस्ताक्षर ग्राम पंचायत छोटीरा  
नाम जबपत्र प्रबालय दिव्याधिकार  
सरपंच  
सील

2) सदस्य

अध्यक्ष  
वन समिति  
छोटीरा

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

3) सदस्य

बुधरा

4) सदस्य

सदस्य

5) सदस्य

(A)

## प्रदर्श - ब

ग्राम समा कोडोली की बैठक दिनांक 23.09.2016 का कार्यवाही विवरण  
ग्राम कोडोली  
स्थान कोडोली

आज दिनांक 23.09.2016 को ग्राम कोडोली के सरपंच श्री/श्रीमती छिमुला की अध्यक्षता में ग्राम समा की बैठक आहुत की गयी है। इस बैठक में ग्राम समा का वन समिति कोडोली के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम कोडोली में आवेदक/एजेंसी/कार्यालयों पावर लाइसेंस (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपर्वतन हेतु 14.00 वनभूमि तथा 2 है। राजस्व वनभूमि कुल 14.00 है। वन भूमि को मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपर्वतित क्रिए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम समा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।
3. इस वन व्यपर्वतन प्रकरण के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि लोहांगुला वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्पारिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परम्परागत दनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

### अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत दनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारिक का नाम	रकम (हे.मे.)
-	<u>कोडोली</u>	<u>विरंक</u>	<u>निरुद्ध</u>

अतः यह एकमत से ग्राम समा में निर्णय लिया गया है कि 14.00 है। वनभूमि तथा 2 है। राजस्व वनभूमि कुल योग 14.00 है। वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स (आवेदक/एजेंसी/कार्यालयों पावर लाइसेंस) खो अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपर्वतित की जावे।

संलग्न :- ग्राम समा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान सूची :-

ग्राम कोडोली  
वन अधिकार समिति  
कोडोली

हस्ताक्षर छिमुला  
नाम छिमुला सरपंच  
सरपंच ग्राम पंचायत-कोडोली  
सील जनपद राजपता-जोरामा  
छिमुला-बस्तर  
हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(A)

प्रदर्श - ब

ग्राम सभा - थानोरा की बैठक दिनांक 21/09/2016 का कार्यवाही विवरण  
ग्राम थानोरा  
स्थान थानोरा

आज दिनांक 21/09/2016 को ग्राम थानोरा के सरपंच श्री/ श्रीमती अदिता मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहुत की गयी है। इस बैठक में ग्राम सभा का वन समिति थानोरा के सदस्य 80% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम थानोरा में आवेदक/एजेंसीश्री विजय पाठर लिंगमे (ग्रामीणीकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपर्वतन हेतु 52.020 हेक्टर वनभूमि तथा 0 है। राजस्व वनभूमि कुल 42.020 है। वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपर्वतित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई है।
3. इस वन व्यपर्वतन प्रकरण के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि लौट आगले वर्ष रखने पर्दू भूमि कार्य के व्यपर्वतन के लिए प्रस्तावित है, मैं कोई भी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वनभूमि पर कृपि कार्य आवास या अन्य पारम्पारिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यवित्तगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारिक का नाम	रकमा (ड.मे)
1	थानोरा	पिंकु	पिंकु

आरे यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 42.020 है। वनभूमि तथा 0 है। राजस्व वनभूमि कल गोग 52.020 है, वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसस (आवेदक/एजेंसी) विजय पाठर लिंगमे को अन्य प्रकलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपर्वतित की जायगी।

संलग्न - ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1) मुख्यमंत्री अध्यक्ष  
वन अधिकार समिति थानोरा

2) हस्ताक्षर  
वन अधिकार समिति थानोरा

3) हस्ताक्षर/अंगूठा निशान  
वन अधिकार समिति थानोरा

4) हस्ताक्षर/अंगूठा निशान  
वन अधिकार समिति थानोरा

5) हस्ताक्षर/अंगूठा निशान  
वन अधिकार समिति थानोरा

हस्ताक्षर ग्राम पंचायत थानोरा  
नाम जनप्रबोधन परिषद विद्युतपुर  
सरपंच  
सील

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

## प्रमाण पत्र

मसर्ता श्री बजरंग पादवर एण्ड रॉटेर लिमिटेड का लौह अयस्क का खनन कार्य हेतु नारायणपुर जिला में नारायणपुर वनमण्डल के कोडोली गांव के वन भूमि व्यवर्तन हेतु 14.00 हेतु वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

16. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का भालन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि 14.00 हेतु एवं/राजस्व एवं भूमि 0.00 हेतु जो इस कार्य हेतु व्यवर्तन की जानी है तथा ग्राम कोडोली तहसील नारायणपुर में स्थित है, में लदमुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्रामसभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23.09.2016 (प्रदर्श "अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जोर्च प्रतिवेदन (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

17. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव 23.09.2016 ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति दिमला की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23.09.2016 रखा था (कई गांव होने पर ग्रत्येक का टिकरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें 70 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कर विस्तार के समझाई रखा हिन्दी भाषा स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

## अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में पदप्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकारी पत्र मान्यता धारक का नाम	रुक्तब्य (है मै)
1	कोडोली	सिंहक	निरक

18. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी यो एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

19. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराय प्रस्ताव दिनांक 23.09.2016 अनुसार ऐसे विलूप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यवर्तन हेतु प्रश्नधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित है।

20. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 23.9.2016 / दिनांक 23.9.2016 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(टायपरिलेस लाइनवानी) ८/५/२०१६  
कलेक्टर

दिनांक

एवं  
अध्यक्ष - जिला वन अधिकार समिति

जिला - नारायणपुर  
(सील)

## प्रमाण पत्र

मलसर्स श्री बजरंग घावर एण्ड स्पॉत लिमिटेड का लौह अयरक का खनन कार्य हेतु नारायणपुर ज़िले में नारायणपुर गनमण्डल के धनोरा नांव के दन भूमि व्यपर्वतन हेतु 52.020 हेठो दन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का वन प्रतिवेदन

11. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सार्वपूर्ण प्रक्रिया का वन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की दनभूमि 52.020 हेठो एवं / राजस्व वन भूमि 0.00 हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपर्वती की जाती है तथा ग्राम धनोरा तहसील नारायणपुर में स्थित है। मैं तदनुसार यह कार्यपाही पूर्ण की गयी है।

ग्रामसभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 21.09.2016 (प्रदर्श "अ") एवं दन तथा राजराव विवाह का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

12. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव 21.09.2016 ग्राम के सरमंच श्री/श्रीमति सरिता मरकाम की अधिकता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.09.2016 रखा गया था (कई गोद होने पर प्रत्येक का विवरण ते दिनांक सहित) एवं इसमें 80 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के लियान्नयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रगाढ़ से अवगत कर विस्तार के सामडाइस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा भैंदी गयी। वह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

## अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में पदप्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवास निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकारी पत्र मान्यता धारक का नाम	रकम (हे.मे.)
1	धनोरा	निरंक	निरंक

13. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चाँ एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

14. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 21.09.2016 अनुसार ऐसे विलूप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपर्वतन हेतु प्रश्नधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित है।

15. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 21.9.2016 / दिनांक 21.9.2016 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपर्वतन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(टामनीसह सानवाडा)  
कलेक्टर  
एवं  
अध्यक्ष — जिला बन अधिकार समिति

जिला — नारायणपुर  
(सील)

दिनांक